संपादकीय जागरण

गुरुवार, 1 नवंबर, 2018 : कार्तिक कृष्ण 8 वि. 2075

आत्मिक शांति से ही प्रसन्नता का द्वार खुलता है

टकराव टालिए

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मतभेद बढ़ना कोई शुभ संकेत नहीं। दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि मतभेद रहते हुए भी मिलकर काम करने और अर्थव्यवस्था को संबल देने की सूरत कैसे बने। आखिर जब दोनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना है तब फिर ऐसी कोई राह निकालना कठिन क्यों होना चाहिए जिससे सभी के हितों की पूर्ति हो? यह सही है कि रिजर्व बैंक एक स्वायत्त नियामक संस्था है, लेकिन उसकी भी जवाबदेही बनती है। उसकी जवाबदेही शासन के प्रति भी बनती है, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जवाब-तलब चुनी गई सरकार से ही किया जाएगा। सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मतभेद नए नहीं हैं। अभी हाल में दोनों के बीच मतभेद तब उभर आए थे जब पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। तब रिजर्व बैंक ने अधिकारों की कमी का सवाल उठाया था जिस पर सरकार की ओर से कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नियामक संस्था वही है और वह सभी वांछित अधिकारों से लैस भी है। रिजर्व बैंक इससे सहमत नहीं दिखा, लेकिन जब यह माना जा रहा था कि मतभेद दूर हो गए हैं तब वे फिर से न केवल उभर आए, बल्कि एक तरह के टकराव में भी तब्दील होते दिख रहे हैं। इस बार मतभेद के कारण करीब दर्जन भर मसले बताए जा रहे हैं। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यदि हर मामले में दोनों का रुख-रवैया एक-दूसरे के विपरीत दिखेगा तो फिर इसी नतीजे पर पहुंचने में आसानी होगी कि किसी न किसी स्तर पर विवाद बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मतभेदों की स्थिति में सहमति की राह खोजना तभी कठिन होता है जब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की जाती।

बैंकों के घोटाले और डूबे हुए कर्ज के मामले में रिजर्व बैंक की दलील कुछ भी हो, आम धारणा यही है कि बैंकों की निगरानी और नियमन का काम सही तरीके से नहीं किया जा सका। आखिर इस सवाल का जवाब रिजर्व बैंक नहीं तो और कौन देगा कि संदिग्ध किस्म के तथाकथित उद्यमियों को बड़े पैमाने पर कर्ज कैसे बंटते रहे? निःसंदेह बढ़ते एनपीए के चलते ऐसे उपाय समय की मांग हैं कि कर्ज एनपीए में तब्दील न होने पाए, लेकिन अगर सख्त उपायों के कारण कर्ज मिलने ही मुश्किल हो जाएंगे तो फिर अभीष्ट की पूर्ति होने वाली नहीं है। यह ठीक नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियमन को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक विपरीत छोर पर दिख रहे हैं। यह स्थिति गैर बैंकिग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आइएल एंड एफएस के संकट में फंसने के बाद बनी है। ऐसा लगता है कि समस्या फैसलों को लेकर नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीकों को लेकर अधिक है। यह ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो सके, लेकिन इसके लिए दोनों ही पक्षों को समाधान तलाशने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। कारोबारी सुगमता सूचकांक में एक और लंबी छलांग के बीच यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि सरकार और रिजर्व बैंक में तनातनी दिखे।

आत्मघाती बेपरवाही

वायु और जल प्रदूषण को लेकर सरकारी तंत्र और न्यायपालिका की तमाम सक्रियता के बावजूद इस भयावह खतरे के प्रति नागरिक चेतना का अभाव चिंताजनक है। जानते-समझते हुए भी कि आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती, अधिकतर लोग प्रदूषण के प्रति आंखें मूंद लेने की मनोदशा में नजर आते हैं। दरअसल, यह बेपरवाही उस परंपरागत मानसिकता का विस्तार है कि हर समस्या के समाधान के लिए सरकार जिम्मेदार है। प्रदूषण की समस्या अब किसी हद तक बेकाबू नजर आने लगी है। दशकों तक हर स्तर पर इस समस्या को नजरअंदाज किया गया। बात बहुत बिगड़ जाने पर सरकार तो अपनी शैली में सक्रिय हुई, पर इसे लेकर नागरिकों में अब भी दायित्वबोध का अभाव दिखता है। छोटे-छोटे योगदान से प्रदूषण के खतरे को बैकफुट पर किया जा सकता है।

> यदि हर व्यक्ति एक पौधा रोपकर उसकी रक्षा और पोषण की जिम्मेदारी ले ले तो कुछ सालों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है

सर्दी के दस्तक देते ही दिल्ली का जनजीवन स्मॉग की चपेट में आने लगा है जबकि लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आगरा और गोरखपुर जैसे शहर दिल्ली के पीछे इस घातक मुसीबत के मुहाने पर खड़े हैं। प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह अनुशासनहीन और गैर जवाबदेह जीवनशैली है। अब बचने का एक ही रास्ता है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक जंग का हिस्सा बने। छोटी-छोटी कई एहतियात बरतने की जरूरत है यद्यपि सबसे जरूरी पहलू है, ग्रीन कवर। पौधरोपण को जुनून की हद तक आदत बनाना होगा। वृक्ष हवा का जहर सोखकर उसे प्राणवायु में तब्दील करते हैं। यदि हर व्यक्ति एक पौधा रोपकर उसकी रक्षा और पोषण की जिम्मेदारी ले ले तो क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अंबाती रायुडू के रूप में भारत को चौथे नंबर के लिए एक भरोसेमंद बल्लेबाज मिल गया है?

आज का सवाल
क्या देश में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' जैसे स्मारकों का निर्माण किया जाना चाहिए?

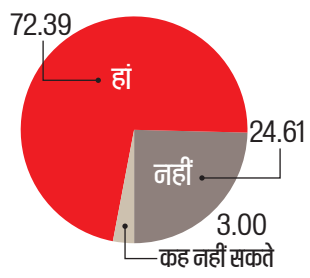

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भाजपा की पिच पर खेलती कांग्रेस

प्रदीप सिंह

राहुल गांधी वह बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो हैं नहीं और इसी कारण जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई गंभीर मुद्दा आता है उनकी रामनामी चादर गिर जाती है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी में खुद को नुकसान पहुंचाने की अद्भुत क्षमता है। मान लीजिए कि नेताओं के लिए कोई नियमावली बनानी हो और उसमें बताना हो कि सफल नेता बनने के लिए क्या-क्या न करें तो वहां कुछ और लिखने के बजाय लिखा जा सकता है कि जो राहुल गांधी करते हैं वह न करें। इससे आपके सफल नेता बनने की संभावना बढ़ जाएगी। किसी भी युद्ध में वह सामरिक हो या राजनीतिक अपने दुश्मन/ विरोधी की कमजोरियों को जानना और उन पर प्रहार करना अच्छी रणनीति मानी जाती है। राहुल गांधी ऐसे सेनापति हैं जो अपनी ही कमजोरियों को उजागर करते हैं। आरोप लगाकर भाग जाने की कला में वह निष्णात हो गए हैं, परंतु उनके सामने लोकसभा चुनाव से पहले वैकल्पिक विमर्श खड़ा करने की सांघातिक समस्या है। जनेऊधारी ब्राह्मण, शिव भक्त, मंदिर प्रेमी से आगे बढ़कर अब राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वह बेहतर हिंदू हैं। उनका दावा है कि वह हिंदू धर्म को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। इन सब बातों से एक बात साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार है। उसे समझ में आ गया है कि चुनावी राजनीति में धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी समस्या यह है कि उसे कोई भी वैकल्पिक विमर्श हिंदू धर्म के दायरे में ही खड़ा करना होगा। पिछले डेढ़-दो दशक का उसका हिंदू धर्म विरोधी विकल्प खत्म हो गया है। उसके पास अब मुस्लिम सांप्रदायिकता का वह विकल्प भी नहीं है जिसमें हिंदू विरोध दिखे। इसी राजनीति ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उसका बेड़ा गर्क किया था।

कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति राहुल गांधी के भाषणों से दिख रही है वह हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की है। शायद उन्होंने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ेंगे। जाहिर है कि वह भाजपा की पिच पर आकर खेलना चाहते हैं या इसे यों भी कह सकते हैं कि भाजपा ने उन्हें इस पिच पर आने के लिए बाध्य कर दिया। यह ऐसी राजनीतिक रणनीति है जिसमें उन्हें कामयाबी मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा के लिए सांस लेने जैसा स्वाभाविक मुद्दा है। यह उसकी ही नहीं पूरे संघ परिवार की पहचान है। भाजपा के किसी नेता को हिंदुत्ववादी होने के लिए मंदिर पर्यटन, जनेऊ दिखाने या रोज शिवभक्त बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी वह बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो वह हैं नहीं। इसी कारण उनका हिंदुत्व ओढ़ा हुआ है और इसी कारण जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई गंभीर मुद्दा आता है उनकी रामनामी चादर गिर जाती है।

बेहतर हिंदू होने का दावा करने वाले राहुल गांधी से सबरीमाला मामले पर सवाल पूछा गया तो उनके जवाब से असलियत सामने आ गई। उनका जवाब था कि उनकी निजी राय है कि महिलाओं को मंदिर में जाने देना चाहिए, लेकिन केरल में मेरी पार्टी की राय अलग है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी की राय आखिर अध्यक्ष नहीं तो कौन तय करेगा? हिंदुत्व की जमीन पर खेलने के लिए राहुल गांधी को बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उनके पुराने बयान उनका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने अमेरिकी राजदूत से कहा था कि भारत के लिए हिंदू आतंकवाद इस्लामी आतंकवाद से बड़ा खतरा है। यह भी कि मंदिर जाने वाले वहां से निकलकर बस में लड़कियों को छेड़ते हैं। राम सेतु पर उनकी सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं। केरल में उनकी पार्टी के लोगों ने सड़क पर बछड़े को काटा। कर्नाटक में लिंगायत वोट के लिए कांग्रेस ने लिंगायतों के एक वर्ग को हिंदू धर्म से निकालने में संकोच नहीं किया। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी से लोग जानना चाहेंगे कि बेहतर हिंदू होने के बाद अब उनका क्या खयाल है।

अवधेश राजपूत

राहुल गांधी ने हिंदुत्व की पिच पर आकर भाजपा के लिए खेल आसान कर दिया है। भाजपा इस खेल की पुरानी माहिर खिलाड़ी है। राहुल गांधी इस मामले में अभी नौसिखिये हैं। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर पर माहौल गरमा दिया है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दे ने भाजपा का हौसला बढ़ाया है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के जल्द सुनवाई से इन्कार करने के फैसले ने मंदिर समर्थकों की इस भावना को बलवती किया है कि हिंदुओं के मामले पर अदालतों का रुख संवेदनशील नहीं होता। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने सरकार पर अध्यादेश या संसद में विधेयक लाकर राम मंदिर निर्णाण का रास्ता प्रशस्त करने का दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस और उसके मुखिया का इस मुद्दे पर रुख क्या होगा?

राहुल गांधी और उनके सलाहकार एक पुराने विमर्श को नए के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, हिंदूवाद की नहीं। हिंदुत्व एक राजनीतिक अवधारणा है जो वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस हिंदू धर्म की मौलिक परंपरा को मानती है। ऐसा विमर्श पहले भी चलाने की कोशिश हुई, पर कामयाबी नहीं मिली। हालांकि तब इससे करपात्री जी महाराज जैसे बड़े संत जुड़े थे। उस वक्त आर्यसमाज की क्रांतिकारी सोच के जवाब में राम राज्य परिषद ने कहा था कि हम तो सनातन धर्म को मानते हैं। आर्य समाज सनातन धर्म की परंपरा से बाहर जा रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि इससे वह भाजपा को उसके ही अखाड़े में चुनौती दे सकती है।

हिंदुत्व और हिंदूवाद का अंतर एक नकली विमर्श है, जिसका असर टीवी की बहसों और कुछ बुद्धिजीवियों तक सीमित है। आम लोगों के लिए इस अंतर का कोई खास महत्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस तरह का विमर्श चुनावी राजनीति के नजरिये से खड़ा करना सोनिया-राहुल के बस का नहीं है। इंदिरा गांधी तक तो ठीक था, क्योंकि वह आस्था और दृश्यता दोनों के लिहाज से इस तरह का विमर्श गढ़ने में सक्षम थीं। कुछ कमी हो तो वह राष्ट्रवाद की छौंक के साथ इसे पूरा कर लेती थी परंतु राहुल गांधी के पूरे व्यक्तित्व में हिंदू धर्म की वह समझ दिखाई नहीं देती। इसलिए तमाम कोशिश और मंदिर दर्शन के बाद भी उनकी वह अच्छे हिंदू वाली छवि बन नहीं पा रही है। बात आस्था की हो या दृश्यता की, दोनों मोर्चों पर राहुल नाकाम नजर आते हैं। गुजरात के नाडिया में सरदार पटेल की एक सौ बयासी मीटर प्रतिमा के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री का सरदार के चरणों में जलाभिषेक और राहुल गांधी के महाकाल में अभिषेक में अंतर किसी भी सामान्य हिंदू को समझ में आ जाएगा। छवियां आमतौर पर लोगों के मन पर ज्यादा गहरी छाप छोड़ती हैं। पिछले एक साल में अचानक जागा राहुल गांधी का हिंदू प्रेम उन्हें अभी तक उनकी बेहतर हिंदू की छवि नहीं गढ़ पाया है। वैसे भी कहते हैं कि नकल कभी असल का मुकाबला नहीं कर सकती।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

एक और छलांग का मतलब

अमिताभ कांत

हमें उन संकेतकों पर भी तेजी से काम करना होगा जहां हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि यह रैंकिंग कायम रख सकें

कारोबारी मोर्चे पर छोटे एवं मझोले उद्योगों के प्रदर्शन और इससे संबंधित 10 पैमानों के आधार पर विश्व बैंक हर साल ईज ऑफ डुइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा था कि देश को कारोबारी सुगमता की सूची वाले शीर्ष 50 देशों में शामिल कराना है। तब भारत 189 देशों की सूची में 142वें स्थान पर था। ब्रिक्स देशों में वह अंतिम पायदान पर तो आठ दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में छठे स्थान पर था। विश्व बैंक की 2019 की इस सूची में भारत 77वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई देशों में उसे सबसे ऊंची रैंकिंग मिली है। पिछले तीन वर्षों में भारत ने इसमें 65 पायदान की छलांग लगाई है। भारत के आकार और जटिलता वाले कुछ ही देशों को ऐसी सफलता मिली है। इस सूचकांक में सुधार 'मेक इन इंडिया' के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि व्यापार के लिए माहौल बनाने में धारणा का अहम योगदान होता है। इसके लिए लागू किए गए सुधार दर्शाते हैं कि हमने व्यापार के लिए स्वयं को खोला है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में शीर्ष सुधारकों को दर्शाया गया है और निजी क्षेत्र के जानकारों की प्रतिक्रिया से ही रैंकिंग तैयार हुई है। आज देश बिजली, छोटे निवेशकों के संरक्षण और ऋण सुविधा के पैमाने पर शीर्ष 25 देशों में शामिल हो गया है। इसी तरह निर्माण परमिट और विदेशी व्यापार के मामले में चोटी के 80 देशों में से एक है। यह बड़ी उपलब्धि रातोंरात हासिल नहीं हुई है। इसके पीछे कई एजेंसियों की चार वर्षों की कड़ी मेहनत है जिससे ऐसा सुधारवादी माहौल बना है।

कारोबारी सुगमता सूचकांक में उछाल केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के विभिन्न विभागों के सतत प्रयासों का परिणाम है। सुधार की मानसिकता और दृष्टि में परिवर्तन से हमें यह सफलता हासिल हुई है। यह इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि इससे हम और सुधारवादी कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। भावी सुधार इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम उन संकेतकों में सुधार कर पाते हैं या नहीं जिनमें हम अब भी पिछड़े हैं। कारोबारी सुगमता के सभी संकेतकों में से संविदा प्रवर्तन और संपत्ति पंजीकरण में सुधार सबसे जटिल हैं। फिर भी कुछ प्रयास हुए हैं। जैसे-केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 में संशोधन किया है। इसी तरह दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और पंजीकरण तथा म्यूटेशन का ऑनलाइन समाधान तैयार करने में भारी निवेश किया है। ये सभी प्रयास सही दिशा में केवल पहले कदम के तौर पर हैं। ड्रइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक विवाद सुलझाने में औसतन चार से अधिक वर्ष लगते हैं। संपत्ति का स्वामित्व खोजने और नए मालिक के नाम पर संपत्ति को म्यूटेट करने में भी हफ्तों लग जाते हैं। इनमें लगने वाला समय ही स्वयं बताता है कि हम इनमें क्यों पिछड़े हुए हैं। इससे निपटने के लिए नई तकनीक और प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा सकती है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से सार्वजनिक पहुंच में सुधार हो सकता है और ई कोर्ट प्रबंधन प्रणालियों को शुरू करने से ऑटोमेशन के माध्यम से कुछ हद तक प्रक्रियाएं सुचारू हो सकती हैं। वाणिज्यिक न्यायालय विवाद समाधान को तब तक तेजी नहीं दे सकते जब तक न्यायाधीशों को व्यावसायिक मामलों में प्रशिक्षित न किया जाए। साथ ही उन्हें अदालतें और सहायक कर्मचारी एवं संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे, क्योंकि वास्तव में उन्हें एक तीव्र विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने हेतु इनकी आवश्यकता होती है। मौजूदा न्यायाधीशों को वाणिज्यिक विवादों पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य सौंपना तब तक उपयोगी नहीं होगा जब तक वे विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों के प्रति समर्पित नहीं होते।

भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण उपयोगी अवश्य हैं, लेकिन वे अपने आप में प्रभावी नहीं हैं। एक भूमि खरीदार भूमि अभिलेख, अदालत के रिकॉर्ड, संपत्ति कर रिकॉर्ड आदि की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जो जमीन खरीद रहा है वह विवादित न हो। यह जानकारी विभिन्न एजेंसियों में डिजिटलीकरण के विभिन्न चरणों में उपलब्ध होती है।

इसके बजाय हमें इन सभी डाटा को उपयोग करने योग्य, खोजने योग्य प्रारूप में एकीकृत करने के लिए एक ऐसी संरचना में भारी निवेश करना होगा जो उपयोगकर्ताओं को एक इंटरफेस के माध्यम से तेजी से विवादों का पता लगाने की सुविधा देती हो। इसके साथ ही हमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नामांतरण प्रक्रिया में तेजी के लिए तहसीलदारों और भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यालयों के कामकाज का संवर्धन करने के लिए सिस्टम में निवेश करना होगा। ध्यान रहे कि अभी न्यायपालिका और सरकार के सभी स्तरों के बीच समेकित और समर्पित कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें समय लगेगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होगी। हम केवल इन्हीं संकेतकों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। सुगम व्यवसाय संबंधी रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भी सुधार की प्रक्रिया जारी है। इसलिए हमें उन संकेतकों पर भी तेजी से काम करने का भी प्रयास करना चाहिए जहां हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम अपनी वर्तमान रैंकिंग को कायम रख सकें।

पिछले तीन वर्षों में हमने जो सीखा है वह यह है कि भारत में आमूलचूल बदलाव लाना तब संभव है जब हम उसके लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं। जब हमने इन प्रयासों को शुरू किया तो कुछ लोग ही इनकी सफलता को लेकर आश्वस्त थे कि विश्व बैंक की सूची में भारत की स्थिति में सुधार हो सकता है। हम न केवल 65 पायदान ऊपर चढ़े हैं, बल्कि हमने अपने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की है। भारत ने सुशासन की ओर कदम बढ़ाए हैं। अच्छी नीतियां बन रही हैं और अच्छी राजनीति हो रही है। कारोबारी सुगमता को लेकर शीर्ष देशों में स्थान बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए उनमें और गति लाने और इसी भावना से कार्य करते रहने की आवश्यकता है। हालांकि आज हम अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कल से हमें भारत में व्यापार विवादों और भूमि प्रबंधन से निपटने के तरीके को सुधारने, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्वयं को समर्पित करना होगा।

(लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रार्थना

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय-समय पर निराशा के क्षण आते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर मनुष्य विकल्पविहीन हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं सूझता और अपना जीवन अंधकारमय लगने लगता है। कई बार मनोचिकित्सज्ञों-विशेषज्ञों की राय भी उनकी निराशा का अंत नहीं कर पाती। ऐसे समय में सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य के लिए वरदान साबित होती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मनुष्य को न केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि उसमें जीवन को जीने का एक नया नजरिया भी विकसित होता है। प्रार्थना निराशा-अवसाद से लड़ने का एक कारगर तरीका है। प्रार्थना में मनुष्य अपने दिमाग से आगे निकलकर बाहर से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। प्रार्थना में मनुष्य अपनी गलतियों, अवगुणों और दोषों को स्वीकार करता है और सच्चे मन से प्रभु से क्षमा मांगता है। ईश्वर न केवल उसकी पिछली गलतियों को माफ कर देते हैं, बल्कि भविष्य की राह दिखाते हुए उसे अपना आशीर्वाद भी देते हैं।

विश्वास के बगैर प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं होता। प्रार्थना में विश्वास अतिआवश्यक है। विश्वास से भरा मनुष्य ही जानता है कि उसके भगवान सर्वशक्तिमान हैं और वे उसके साथ अवश्य न्याय करेंगे। यानी प्रार्थना में विश्वास और ईमानदारी हो तो मनुष्य सीधे प्रभु से जुड़ जाता है। सच्चाई यह है कि मनुष्य द्वारा अपने मन की लौ को ईश्वर के साथ लगा देने भर से उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। प्रार्थना से दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। यहां तक कि प्रार्थना की शक्ति से स्वयं ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। जहां प्रार्थना से मन को शांति और अपार सुख मिलता है, वहीं स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना उसके प्रति हमारी सच्ची निष्ठा को भी दर्शाता है।

प्रार्थना करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। सर्व शक्तिमान ईश्वर के आगे किसी भी समय नतमस्तक हुआ जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि पूजा स्थल पर जाकर ही हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। ईश्वर को हम कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय सच्चे मन से याद कर सकते हैं। बिना दिखावा किए श्रद्धा भाव से ईश्वर का स्मरण करना ही प्रार्थना है।

शंभूनाथ पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

पटेल का स्मरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित लेख 'एकजुटता के सूत्रधार का स्मरण' पढ़ा। उन्होंने सरदार पटेल के विविध आयामी व्यक्तित्व तथा कृतित्व को बारीकी से विश्लेषित किया है। वास्तव में रियासतों में बंटे देश को सर्वसम्मति से एकजुट करके सुदृढ़ तथा सशक्त भारत के निर्माण में सरदार पटेल का अविस्मरणीय योगदान है। राजनीति से अलग एक समृद्ध राष्ट्र की उनकी संकल्पना में गांव, गरीब, श्रमिक, किसान, महिलाएं तथा युवा सभी के लिए एक विजन तथा संकल्प था। धरती पुत्र सरदार पटेल को 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के माध्यम से पुनः स्थापित करना और श्रद्धांजलि देना निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। एक लंबे समय के बाद अब पुनः जन-मन में भारत के गौरवशाली अतीत को जानने का भाव जगा है, ऐसे में एकता के सूत्रधार का यह स्मरण और सम्मान नए भारत के निर्माण में सहायक होगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हमें आगे बढ़ने का लक्ष्य भी देगी। आज यह भी आवश्यक है कि भारतीय परंपरा के अन्य गौरवशाली पक्षों को भी इसी रूप में दर्शाया-बताया जाए।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

दिल्ली में वायु प्रदूषण

आज दिल्ली बुरी तरह से स्मॉग की चादर में है। हो सकता है कुछ प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली से सटे राज्यों की देन हो। लेकिन, दिल्ली सरकार का हरियाणा के किसानों को पराली जलाने पर कोसना केवल अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ने जैसा है। क्योंकि हरियाणा सरकार के आकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 50 प्रतिशत पराली जलाने में कमी आई है और दूसरी मुख्य बात यह कि ऐसी क्या वजह है कि सारे राज्यों का धुआं दिल्ली में ही आकर फंस जाता है और दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाता? दिल्ली सरकार को दिल्ली में प्रदूषित यमुना, सारे डंपिंग साइट्स, सड़कों पर धूल, बड़े- छोटे वाहनों की फिटनेस, भवन-निर्माण आदि से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए न कि अन्य राज्यों व केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति कर के। दिल्ली सरकार को समय रहते प्रदूषण रोकथाम पर कारगर कदम उठाने चाहिए।

दीपक गौतम, सोनीपत

सम्मान में देरी

सरदार बल्लभाई पटेल ने अल्प समय में अपनी व अपनी टोली की कड़ी मेहनत से 550 से भी ज्यादा टुकड़ों में विभाजित इस धरा को एकसाथ लाकर 1947 में ही वर्तमान भारत की खंडित न होने वाली तस्वीर पेश कर दी थी और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी अंतिम सांस तक काम किया। उन्हें सम्मान देने में शायद हमने देरी की है और उनके योगदान को समझने में देरी की है। उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना नई पीढ़ी का मार्गदर्शन तो करेगी ही साथ ही यह याद भी दिलाएगी कि यही हैं वो महापुरुष जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर लकीरें खींचकर अपना हक लिया था।

सतीश त्यागी काकड़ा, गाजियाबाद

गौरवपूर्ण क्षण

भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे शख्सियत थे, जिन्होंने तत्कालीन विभाजन के समय देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। पटेल के व्यक्तित्व को हमेशा सराहा गया। देशी रियासतों में शामिल जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भारतीय संघ से जोड़ने के लिए उनको तमाम मुश्किलें आई किंतु वे इस कार्य में सफल हुए और सदा एकता के प्रति समर्पित रहे। यही कारण है कि देश में सरदार पटेल की याद में विश्व के सबसे ऊंचे स्टैच्यू की नींव रखी गई। विश्व पटल पर भारत के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण है।

अंकित कुंवर, इग्नू विश्वविद्यालय, दिल्ली

हानिकारक प्लास्टिक

प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि हजारों सालों तक ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, अन्य पदार्थों की तरह विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के कचरे के समाधान के लिए कई लोग इसे जला देते हैं, लेकिन इसको जलाने से वह सारे केमिकल हवा में फैल जाते हैं, जिससे यह बना है और इसी से वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक को सड़ने में हजार वर्षों का समय लग जाता है, उपयोग के बाद इसको यहां -वहां फेंक दिया जाता है। हालांकि सड़क बनाने और दीवार बनाने में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। प्लास्टिक को इसी तरह अन्य जगह इस्तेमाल करके इसके कचरे की समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसके उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना प्रथम प्रयास में शामिल होना चाहिए। दुनिया का हर देश प्लास्टिक प्रदूषण की विनाशकारी समस्याओं से जूझ रहा है तो क्यों न हम सब प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें।

diwakardas43806@gmail.com

नक्सलियों में बौखलाहट

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पूर्व नक्सलियों का विरोध चरम पर है। राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के सात जिलों और राजनांदगांव जिले की कुल 18 सीटों पर मतदान 12 नवंबर को होना है, किन्तु नक्सलियों के लोकतंत्र पर हमले लगातार जारी हैं। दंतेवाड़ा में 30 अक्टूबर को नक्सलियों ने 2 जवानों और चुनाव का कवरेज कर रहे दूरदर्शन के कैमरामैन की जघन्य हत्या कर दी। यह हमला देश के कानून और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर है। इससे नक्सलियों के नापाक और घातक इरादे जाहिर होते हैं। यह घटते जनाधार और बढ़ते कानूनी शिकंजे का नतीजा है। सख्ती से नक्सलियों की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है।

sonimohit895@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

ईश्वर मेरे भारत को असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह जैसे लोगों से बचाए। ये जब भी मुंह खोलते हैं घृणा, बर्बादी, गुस्सा, नफरत उगलते हैं। देश सहिष्णुता और समझदारी से चलता है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, रास्ता निकलेगा।

हरीश रावत@harishrawatcmuk

हे ईश्वर ...ये आपके लोग अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए आपके ही विरोधी हो गए है। इन्हें सद्बुद्धि दो।

शांडिल्य गिरिराज सिंह@girirajsinghbjp

औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती की अनुमति तभी तक ठीक है, जब तक उस पर पूर्ण नियंत्रण हो। अन्यथा नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता नशाखोरी और चिलमबाजी को प्रोत्साहित करेगी जो लोगों को मानसिक-शारीरिक रूप से बीमार करेगी।

अखिलेश यादव@yadavakhilesh

गुजरात में तो कोई चुनाव नहीं है फिर वहां पटेल की प्रतिमा बनवाना राजनीति कैसे हो गई? और अगर आपको लगता है कि यह प्रतिमा आगामी चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाएगी तो जरा सोचिए कि पटेल के इतना प्रभावशाली होने के बावजूद पहले की सरकार ने सालों तक उन्हे हाशि